

# विश्व पर्यावरण दविस 2024

## प्रलिम्सि के लिये:

<u>वशिव पर्यावरण दविस,</u> संयुक्त राष्ट्र सभा, <u>स्टॉकहोम कन्वेंशन,</u> COP, NAP, <u>लाइफ आंदोलन</u> ।

# मेन्स के लिये:

विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता और संबंधित पहल

स्रोत: द हिंदू

# चर्चा में क्यों?

पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बद्धाने के लिये प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।

 वनों की कटाई को नियंत्रित करने और जैवविधिता को बहाल करने की एक उल्लेखनीय पहल में, दो पर्यावरणविदों ने बाघ अभयारण्यों के भीतर भारत के पहले बायोस्फीयर के निर्माण का नेतृत्व किया है।

# टाइगर रज़िर्व में भारत का पहला बायोस्फीयर:

- हाल ही में दो पर्यावरणविदों, जय धर गुप्ता और विजय धस्माना ने उत्तराखंड के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक टाइगर रिज़र्व में भारत का पहला बायोसफीयर बनाया, जिसे राजाजी राघाटी बायोसफीयर (RRB) कहा जाता है।
- बायोस्फीयर एक 35 एकड़ की निजी वन पहल है जिसका उद्देश्य क्षेत्र को शिकारियों और खनन से बचाते हुए देशी वृक्षों की दुर्लभ और लुपतप्राय प्रजातियों की पहचान करना और उन्हें पुनर्जीवित करना है।
- RRB के लिये निर्धारित भूमि पहले बंजर और क्षरित अवस्था में थी।
- वे <u>पश्चिमी घाट</u> के साथ महाराष्ट्र के पुणे के पास **सहयाद्री टाइगर रज़िर्व** के बफर जोन में **कोयना नदी** के ऊपर एक दूसरा बायोस्फीयर भी विकसति कर रहे हैं।

## 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान'

- इसकी शुरुआत भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाकर की थी।
- उन्होंने देश वाशियों से आग्रह किया कि वे संधारणीय जीवनशैली अपनाकर प्रकृति की रक्षा करें और अपने ग्रह को बेहतर बनाने में योगदान दें।

# विश्व पर्यावरण दविस के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- परचिय:
  - ॰ संयुक्त राष्ट्र सभा ने वर्ष 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की, जो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम कन्वेंशन का प्रथम दिन था।
  - विश्व पर्यावरण दिवस (WED) प्रतिवर्ष एक विशिष्ट थीम और नारे के साथ मनाया जाता है जो उस समय के प्रमुख पर्यावरणीय
    मुद्दों पर केंद्रित होता है।
    - वर्ष 2024 में WED की मेज़बानी **सऊदी अरब** करेगा।

- भारत ने वर्ष 2018 में 'प्लास्टिक प्रदूषण को हराएँ' थीम के अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस के 45वें समारोह की मेज़बानी की।
- वर्ष 2021 में WED समारोह ने पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक (2021-2030) की शुरुआत की, जो वनों से लेकर खेतों तक, परवतों की चोटियों से लेकर सागर की गहराई तक अरबों हेक्ट्रेयर भूमि को पुनरजीवित करने का एक वैश्विक मिशन है।

#### वरष 2024 की थीम:

- ॰ भूम पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता।
- ॰ वर्ष 2024 <u>मरुस्थलीकरण रोकथाम हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UN Convention to Combat Desertification-UNCCD)</u> की 30वीं वर्षगाँठ भी होगी।
- भूमि पुनर्दधार का महत्त्वः
  - पर्यावरणीय क्षति को उलटना: भूमि क्षरण, सूखा और मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना।
  - नविश पर उच्च प्रतिफल: नविश किये गए प्रत्येक डॉलर से स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र से 30 अमेरिकी डॉलर तक का लाभ परापत हो सकता है।
  - समुदायों को बढ़ावा देना: रोज़गार सृजन करता है, निर्धनता को कम करता है और आजीविका में सुधार करता है।
  - लचीलापन को मज़बूत करना: समुदायों को चरम मौसम की घटनाओं का बेहतर ढंग से सामना करने में सहायता करता है।
  - जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करता है: मिट्टी में कार्बन भंडारण क्षमता में वृद्धि करता है और तापमान वृद्धि की गति को धीमा करता है।
  - जैववविधिता की रक्षा: केवल 15% क्षरित भूमि को बहाल करने से अपेक्षित प्रजातियों के विलुप्त होने के महत्त्वपूर्ण हिस्से को रोका जा सकता है।

# पर्यावरणीय स्थरिता में भारत का योगदान क्या है?

- <u>मशिन LiFE</u>
- राष्ट्रीय हरति भारत मिशन (GIM): इसका उद्देश्य 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन/वृक्ष आवरण को बढ़ाना तथा अन्य 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन/वृक्ष आवरण की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (NAP): इसके अंतर्गत वर्ष 2020 तक 21.47 मलियिन हेक्टेयर भूमि पर वनरोपण क्या गया है।
- राष्ट्रीय जैववविधिता कार्य योजना
- नगर वन योजना (शहरी वन योजना): यह शहरों और कस्बों के भीतर छोटे शहरी वन या "नगर वन" विकसित करने पर केंद्रित है।
- स्कूल नर्सरी योजना: यह स्कूलों को अपनी नर्सरी विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करती है।
- <u>CAMPA कोष</u>: वनरोपण और पुनर्जनन गतविधियों आदि को बढ़ावा देने के लिये प्रतिपूरिक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority- CAMPA) की स्थापना की गई है।
  - ॰ ये कार्यक्रम अनुपयोगी, खाली और बंजर भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देते हैं।
- आर्द्रभूमि संरक्षणः
  - ं भारत ने कर्नाटक और तमलिनाडु में नए स्थलों को नामित करके जनवरी 2024 तक अपने**रामसर स्थलों** की संख्या को **80 तक** बढा दिया।
    - भारत की 75वीं स्वतंत्रता वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में अगस्त 2022 में 11 आर्दरभूमियाँ शामिल की गई।
  - ॰ **वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल** वेटलैंड्स प्रबंधकों और हतिधारकों के लिये ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करता है तथा बहुमूल्य जानकारी एवं संसाधन प्रदान करता है।

### वन एवं वन्यजीव संरक्षण:

- ॰ पिछले 15 वर्षों में शुद्ध वन क्षेत्र वृद्धि में भारत में तीसरे स्थान पर है।
- भारत वन संथिति रिपीरट (India State of Forest Report- ISFR) 2021 के अनुसार, भारत का वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है।
- ॰ भारत ने <mark>प्रोजेक्ट टाइगर</mark> के **50 वर्ष और प्रोजेक्ट एलीफेंट के 30 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया,** जिससे प्रजातियों के संरक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता प्रदर्शति हुई।
- ॰ <u>'गरीन करेडिट परोगराम'</u> की <mark>शुरुआत</mark> वृक्षारोपण को प्रोत्साहति करने तथा बंजर वन भूमि के पुनरुद्धार के लिये की गई है, जिससे जलवायु काररवाई पहल में योगदान मिलेगा।

#### मैंग्रोव पुनरुद्धार:

- े भारत सर<mark>कार ने त</mark>टीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में <mark>मैंग्रोव वनों</mark> के **संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये संवर्द्धनात्मक एवं विनियामक** उपाय लागू किये हैं।
- ॰ राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 'मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों का संरक्षण एवं प्रबंधन' नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना कार्यानवित की जा रही है।
- मैंग्रोव को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिये केंद्रीय बजट 2023-24 में तटीय पर्यावास एवं ठोस आमदनी हेतु मैंग्रोव पहल (Mangrove Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Incomes MISHTI) की घोषणा की गई थी।

#### एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध:

- ॰ सरकार ने <u>प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 202</u>4 के माध्यम से **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016** में संशोधन किया गया हैं।
- नियम चिह्निति एकल-उपयोग प्लास्टिक (Single-Use Plastic-SUP) के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हैं।
- नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा:

- जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के नविश के साथ शुरू किया गया राष्ट्रीय हरति हाइड्रोजन मशिन भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिये एक बड़ा परविरतनकारी कदम होगा।
- इस मशिन का उद्देश्य भारत को हरति हाइड्रोजन उत्पादन और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाना है।
- ॰ यह प्रयास **जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को महत्त्वपूर्ण रूप से कम करेगा, अर्थव्यवस्था को कार्बन-मुक्त करेगा** तथा वैश्विक सवचछ ऊरजा परविरतन को परेरित करेगा।
- भारत की वैश्विक पहलें:
  - ॰ भारत **सर्कुलर इकोनॉमी और संसाधन दक्षता के लिये वैश्विक गठबंधन (Global Alliance for Circular Economy and Resource Efficiency- GACERE)** तथा **अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पैनल (International Resource Panel- IRP)** की संचालन समिति का सदसय है।
    - ये मंच वैश्विक एवं न्यायसंगत <u>चक्रीय अर्थव्यवस्था</u> (Circular Economy) परिवर्तन तथा सतत् प्राकृतिक संसाधन परबंधन की वकालत करते हैं।
  - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance- ISA) की छठी सभा 31 अक्तूबर 2023 को **नई दिल्ली** में आयोजित की गई, जिसमें **116 सदस्य** और हस्ताक्षरकर्त्ता देशों के मंत्री एवं प्रतिनिधि भाग लेंगे।

# पर्यावरण दविस पर कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट:

- कोयला मंत्रालय के तहत कोयला तथा लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, कोयला-धारक क्षेत्रों और उसके आसपास के क्षेत्रों
  में व्यापक वृक्षारोपण प्रयासों के माध्यम से खनन में छूट वाले क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के उपायों को क्रियान्वित कर रहे हैं।
- कोयला मंत्रालय ने "कोयला एवं लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में हरित पहल" (Greening Initiative in Coal & Lignite PSUs) शीर्षक के नाम पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें खनन द्वारा नष्ट हुई भूमि को बहाल करने और पुनर्जीवित करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है।
  - ॰ रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि **कोयला क्षेत्र भू<u>म पुनरुद्धार</u> के ल**क्ष्यों को आगे बढ़ाने तथा **पर्यावरणीय स्थरिता** को बढ़ावा देने में महततवपुरण भूमकि। निभा सकता है।
  - कोयला/लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने कोयला खनन क्षेत्रों में और उसके आसपास लगभग 50,000 हेक्ट्रेयर काहरित आवरण बनाया है। इसमें कोयला रहित भूमि को पुनः प्राप्त करना तथा खदान पट्टे के आंतरिक और बाह्य भाग में वृक्ष लगाना शामिल है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 2.5 मिलियन टन CO2 समतुल्य कार्बन सिक (Carbon Sink) का उत्सर्जन होने का अनुमान है।
  - इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 2.5 से 3.0 बलियिन टन कार्बन सिक बनाने केराष्ट्रीय सूतर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution- NDC) लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता के लिये भारत के हरित आवरण में वृद्धि करना है।

# AQ-AIMS और वायु-प्रवाह ऐप:

विश्व पर्यावरण दिवस पर, **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** ने भारत में बेहतर वायु गुणवत्ता जागरूकता और निगरानी की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया।

- AQ-AIMS (स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली): यह लागत प्रभावी, भारत निर्मित प्रणाली महँगी, जटलि पारंपरिक विधियों की जगह लेती है।
- **वायु-प्रवाह ऐप:** उनका **मोबाइल ऐप** वास्तविक समय <u>वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)</u> डेटा प्रदान करता है, साथ ही इसमें निम्नलखिति विशेषताएँ भी हैं
  - ॰ आसान सेटअप
  - ॰ लाइव डेटा वज़िअलाइज़ेशन
  - आसान समझ के लिये युनिट रूपांतरण
  - ॰ समय या स्थान के आधार पर AQI तुलना
  - ॰ सुवधाजनक पहुँच के लिये मल्टी-डिवाइस समर्थन
  - ॰ गहन जानकारी के लिये डेटा विश्लेषण उपकरण
  - ॰ केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन के लिये दुरस्थ निगरानी
  - ॰ नवीनतम जानकारी के लिये सुवचालित अपडेट

#### • लाभ:

- ॰ कफिायती और उपयोगकर्त्ता के अनुकूल वायु गुणवत्ता नगिरानी।
- ॰ सटीक डेटा के साथ पर्यावरणीय मंजूरी।
- ॰ सूचित निर्णयों (जैसे, उच्च प्रदूषण के दौरान मास्क पहनना) के माध्यम से बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य की संभावना।

#### तकनीकी जानकारी:

- AQ-AIMS को PM (वभिनिन आकार), SO2, NO2, O3, CO, CO2, तापमान और आर्दरता की नगिरानी के लिये मान्य किया गया है।
- ॰ 'एग्रीएनिक्स' कार्यक्रम के तहत C-DAC कोलकाता, TeXMIN (ISM धनबाद) और JM एनवायरोलैब प्राइवेट लिमिटिंड के बीच एक सहयोगी प्रयास के माध्यम से विकसित किया गया।

### दृष्टि मेन्स प्रश्न:

भूम पुनर्स्थापन में भारत की चुनौतयों और अवसरों की व्याख्या कीजयि । पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दशक के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये नीतिगत उपाय सुझाइए ।

## UPSC सविलि सेवा परीकषा, वगित वर्ष के प्रश्न

### [?]?]?]?]?]?]?]:

प्रश्न. 'अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (Intended Nationally Determined Contributions)' पद को कभी-कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? (2016)

- (a) युद्ध-प्रभावति मध्य-पूर्व के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये यूरोपीय देशों द्वारा दिये गए वचन
- (b) जलवाय परविरतन का सामना करने के लिये विशव के देशों दवारा बनाई गई कारय-योजना
- (c) एशियाई अवसंरचना नविश बैंक (एशियन इंफ्रास्ट्रकचर इन्वेस्टमेंट बैंक) की स्थापना करने में सदस्य राष्ट्रों दवारा किया गया पूँजी योगदान
- (d) धारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य-योजना

#### उत्तर: (b)

## प्रश्न. वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

- 1. इस समझौते पर UN के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किये और यह वर्ष 2017 से लागू होगा।
- 2. यह समझौता ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग-पूर्व स्तर (pre-industrial levels) से 2°C या कोशिश करें कि 1.5°C से भी अधिक न हो पाए।
- 3. विकंसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिये विकासशील देशों की सहायता के लिये 2020 से प्रतिवर्ष 1000 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई।

### नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिय-

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

#### उत्तर: (b)

### [?][?][?][?]:

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021)

प्रश्न. "वहनीय (ऐफोर्डेबल), विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच संधारणीय (सस्टेनबल) विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिये अनिवारय है।" भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टिपिणी कीजिये। (2018)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/world-environment-day-2024